विस्तृत क्षेत्रों का प्रयोग यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए नहीं किया जाता है।

पश्चिम बंगाल : राज्य सरकार को यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए शहरी लोगों द्वारा किसी बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की ख़रीद की कोई जानकारी नहीं है।

दादरा व नागर हवेली : गत दो वर्षों से दादरा व नगर हवेली केन्द्र शासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने को पहले ही हतोत्साहित किया गया है। छोटे तथा गरीब किसानों द्वारा अपने फार्मों में केवल फल ईंधन तथा चारे के पेड़ों के मिश्रित बागान लगाए जाते हैं।

लक्षद्वीप : बड़े पैमाने पर भूमि का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। कोई लेन-देन केन्द्रशासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ नहीं उगाए जाते हैं।

गोआ, दमन व द्वीप : इस केन्द्रशासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए किसी कृषि भूमि को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।

असम : राज्य सरकार के पास गैर-कृषि शहरी लोगों द्वारा यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने और कृषि भूमि को खरीदने के बारे में कोई सूचना नहीं है। जिला राजस्व प्राधिकारियों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

उड़ीसा : जानकारी एकत्र की जा रही है।

नागालैण्ड : ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

Price of flats in Saket

3454. SHRI K. GOPALAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi High Court has directed DDA to reduce the price of its self financial flats in Saket in the recent past; if so, details thereof;

(b) how many flats were involved in this regard;

(c) whether DDA complied with directive; if not the reasons therefor;

(d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, whether any amount has been returned to the allottees; if so, details thereof the allottees and amount returned to each allottee; and

(e) if not, whether Government propose to take disciplinary action against Member (Finance) DDA?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, sir. The cost recoverable as per the Delhi High Court's order is as follows:—

Category	Cost recoverable as per the order of the High Court
	Rs.
I (With terrace)	71,100
I (without terrace)	70,100
II	87,900
III	1,19,400

(b) 720 flats.

(c) No, Sir. An appeal has been filed in the Supreme Court and the matter is subjudice.

(d) and (e) Do not arise.

समाज कल्याण बोर्डों का गठन

†3454क. **श्री शरद यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये कार्य करने वाले समाज सेवी संगठनों को दिल्ली प्रशासन द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है जबकि

†पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2908, 3 दिसम्बर, 1986 से स्थानान्तरित।